

Current affairs summary for prelims

12 September, 2024

मौलिक कर्तव्य

संदर्भ: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागु करने के लिए स्पष्ट कानून बनाने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई की है।

अवलोकन:

- अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए न केवल संवैधानिक संशोधनों की बल्कि निरंतर विधायी और कार्यकारी प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों पर निर्देश देने की याचिका को स्थगित कर दिया, क्योंकि उनका स्वरूप न्यायोचित नहीं है।
- मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976, भाग IV-A द्वारा जोडा गया है।
- उद्देश्य: नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाना तथा मौलिक अधिकारों को बढावा देना।
- प्रेरणा : यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान पर आधारित है।

मौलिक कर्तव्यों की सूची

- संविधान का सम्मान करें और संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखें।
- राष्ट्रीय प्रतीक जैसे ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।
- देश की रक्षा करें, यदि आवश्यक हो तो रक्षा सेवाओं में सेवा करें।
- सद्भाव को बढ़ावा दे, लोगों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा दे।
- पर्यावरण का संरक्षण करें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें, मानवतावाद और जिज्ञासा की भावना विकसित करें।
- सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें और हिंसा से बचें।
- उत्कृष्टता के लिए प्रयास करे, गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखें।

उद्देश्य

- नागरिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना, नागरिकों में प्रतिबद्धता को बढावा देना।
- अधिकारों का पुरक बनाना, नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों की भी याद दिलाना।
- राष्ट्रीय एकता को बढावा देंना. एकता का समर्थन करना और राष्ट्रीय प्रतीकों का

चुनौतियां

- गैर-न्यायसंगत: मौलिक कर्तव्यों को न्यायपालिका द्वारा लाग् नहीं किया जा सकता।
- कान्नी ढांचे का अभाव: कोई विशिष्ट कान्न इन कर्तव्यों को लागु नहीं करता है, जिससे व्यावहारिक कार्यान्वयन सीमित हो जाता है।
- कानन की आवश्यकता: प्रभावी प्रवर्तन के लिए विधायी ढांचे और नीतियों की आवश्यकता होती है।
- न्यायिक सीमाएं: न्यायालय विशिष्ट कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन उसे लागू नहीं कर सकते।

सरदार स्वर्ण सिंह समिति

- **गठन**: 1976
- सिफारिश: संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाए।
- उद्देश्य : यह सुनिश्चित करना कि नागरिक राष्ट्र के प्रति नैतिक दायित्वों को पूरा करें।
- परिणाम : सिफारिशों के परिणामस्वरूप 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग IV-A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया।

सेना में एआई

संदर्भ: हाल ही में सियोल में आयोजित REAIM शिखर सम्मेलन में चीन को छोड़कर 60 देशों ने AI सैन्य दिशानिर्देशों का समर्थन किया।

अवलोकन:



Taegeuk, a traditional symbol of Korea, signifies the REAIM Summit's goal of establishing optimal international norms through comprehensive discussions.

- हाल ही में. सियोल में आयोजित REAIM शिखर सम्मेलन में 60 देशों ने AI सैन्य दिशानिर्देशों का समर्थन किया, जिसमें चीन ने भाग नहीं लिया।
- हेग में आयोजित पिछले शिखर सम्मेलन में लगभग 60 देशों ने एक गैर-बाध्यकारी "कार्रवाई के आह्वान" का समर्थन किया था।
- अद्यतन ब्लुप्रिंट में युक्रेन द्वारा एआई-सक्षम ड्रोनों के उपयोग जैसी प्रगति को दर्शाया गया है, तथा इसमें सामूहिक विनाश के हथियारों के एआई प्रसार को रोकने तथा परमाणु हथियारों के उपयोग में मानव नियंत्रण सुनिश्चित करने के उपाय भी शामिल हैं।

रक्षा क्षेत्र में एआई अनुप्रयोग

- खफिया, निगरानी और टोही (आईएसआर):
 - उन्नत डेटा विश्लेषण: एआई उपग्रहों, ड्रोनों और सेंसरों से प्राप्त विशाल मात्रा में डेटा के विश्लेषण में सुधार करता है, जिससे स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ती है।
 - वास्तविक समय निगरानी: एआई प्रणालियां विसंगतियों का पता लगाने के लिए लाइव वीडियो फीड को संसाधित करती हैं, जिससे निगरानी क्षमताओं में सुधार होता है।

स्वायत्त वाहन और ड्रोन:

- एआई-सक्षम ड्रोन: इन ड्रोनों का उपयोग टोही, निगरानी और लक्षित हमलों के लिए किया जाता है और ये जटिल वातावरण में स्वायत्त या अर्ध-स्वायत्त रूप से काम कर सकते हैं।
- स्वचालित सैन्य वाहन: मानव जोखिम को कम करने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए स्वायत्त टैंकों और आपूर्ति वाहनों में एआई का उपयोग किया जाता है।

रसद और इन्वेंटरी प्रबंधन:

- पूर्वानुमानित रखरखाव: एआई उपकरण की खराबी होने से पहले ही उसका पूर्वानुमान लगा लेता है, जिससे समय पर रखरखाव सुनिश्चित होता है और समय
- आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन: एआई लॉजिस्टिक्स मार्गों को अनुकूलित करता है और भंडार का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करता है।









Current affairs summary for prelims

12 September, 2024

साइबर सुरक्षा:

- खतरे का पता लगाना: एआई प्रणालियां वास्तविक समय में साइबर खतरों का पता लगाती हैं और उनका जवाब देती हैं, जिससे सैन्य नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा होती है।
- व्यवहार विश्लेषण: एआई असामान्य पैटर्न के लिए नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है जो सुरक्षा उल्लंघन का संकेत हो सकता है।

• निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस):

- रणनीतिक योजना: एआई विभिन्न परिदृश्यों और परिणामों का अनुकरण करके सैन्य योजना बनाने में सहायता करता है।
- सामिरक निर्णय-निर्माण: एआई कमांडरों को संचालन के दौरान कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करता है।

प्रशिक्षण और विश्लेषण:

- आभासी प्रशिक्षण वातावरण: एआई-संचालित सिमुलेशन सैनिकों और रणनीतिकारों के लिए यथार्थवादी प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करते हैं।
- प्रदर्शन विश्लेषण: एआई प्रशिक्षण के दौरान प्रदर्शन का आकलन करके सुधार के क्षेत्रों की पहचान करता है।

🍃 लाभ

• बढ़ी हुई दक्षता और सटीकता:

- सटीक लक्ष्य निर्धारण: एआई लक्ष्य निर्धारण प्रणालियों की सटीकता को बढ़ाता है, संपार्श्विक क्षति को कम करता है और मिशन की सफलता दर को बढ़ाता है।
- तीव्र निर्णय-प्रक्रिया: एआई डेटा को तीव्र गित से संसाधित करता है, जिससे तीव्र और अधिक सूचित निर्णय लेने की सुविधा मिलती है।

• उन्नत परिचालन क्षमताएं:

- 24/7 निगरानी: एआई प्रणालियाँ बिना थके निरंतर निगरानी प्रदान करती हैं,
 जिससे सुरक्षा और परिचालन तत्परता में सुधार होता है।
- स्वायत्त संचालन: एआई खतरनाक या दुर्गम क्षेत्रों में मानव उपस्थिति की आवश्यकता को कम करता है।

• बेहतर रसद और रखरखाव:

 पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण: एआई उपकरण की आवश्यकताओं और संभावित विफलताओं का पूर्वानुमान लगाता है, तथा रखरखाव कार्यक्रम और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकुलित करता है।

उन्नत खतरा पहचान:

 साइबर सुरक्षा: एआई साइबर खतरों का पता लगाने और उन्हें कम करने की क्षमता में सुधार करता है तथा महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है।

• लागत बचत:

 परिचालन लागत: एआई मानव संसाधन आवश्यकताओं को कम करता है
 और पूर्वानुमानित रखरखाव के माध्यम से उपकरणों के जीवनकाल को बढ़ाता है।

भारत सरकार की पहल

एआई टास्क फोर्स: भारत सरकार ने रक्षा सिहत विभिन्न क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों
 का पता लगाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एआई टास्क फोर्स की स्थापना की है।

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ): डीआरडीओ बेहतर निगरानी, स्वायत्त प्रणालियों और डेटा विश्ठेषण के लिए रक्षा प्रणालियों में एआई को एकीकृत करने पर काम कर रहा है, और प्रौद्योगिकी फर्मों और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है।
- राष्ट्रीय एआई पोर्टल: यह पोर्टल भारत में एआई के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग भी शामिल है तथा यह संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण और सहायता प्रदान करता है।
- रक्षा उत्पादन नीति: यह नीति रक्षा उत्पादन में नवाचार और एआई सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत सैन्य संदर्भों में एआई के जिम्मेदार उपयोग पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सहयोगों में भाग लेता है।

REAIM शिखर सम्मेलन के लक्ष्य

- वैश्विक शासन: शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एआई के दुरुपयोग को रोकने और जिम्मेदार अनुप्रयोगों को सुनिश्चित करने के लिए एआई के सैन्य उपयोग के लिए सहमत मानदंड विकसित करना है।
- दीर्घकालिक प्रभाव: इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इसके जोखिमों और लाभों का समाधान करके सैन्य AI के भविष्य को आकार देना है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने AB PM-JAY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी विरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी।

> अवलोकनः



- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी विरष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दी।
- इस योजना में 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है और नए आयुष्पान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) कार्ड जारी किए गए हैं।
- AB-PMJAY दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है, जो 55 करोड़ व्यक्तियों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रदान करती है।
- यह योजना अब 37 लाख आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक महिला कार्यकर्ताओं
 और उनके परिवारों को कवर कर चुकी है तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करती है।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)

अवलोकन

• **लॉन्च तिथि:** 23 सितंबर, 2018

• स्थान: रांची, झारखंड











Current affairs summary for prelims

12 September, 2024

- उद्देश्य: सुलभ एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना; 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लक्षित करते हुए विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य योजना है।
- महत्व: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी): यह व्यापक एवं एकीकृत माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल सेवा वितरण की दिशा में एक कदम है।

🕨 मुख्य लाभ-

- कवरेज: द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5 लाख तक का बीमा प्रदान करना।
- लाभार्थी: 10.74 करोड़ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार (लगभग 50 करोड़ व्यक्ति)
 शामिल होंगे।
- सेवा तक पहंच: सेवा केंद्र पर नकदी रहित और कागज रहित होता है।
- वित्तीय संरक्षण: इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पर होने वाले विनाशकारी व्यय को कम करना तथा स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं से उत्पन्न वित्तीय जोखिम को कम करना है।

🕨 विशेषताएँ

- देखभाल की निरंतरता: प्राथमिक देखभाल के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) और द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए AB-PMJAY को जोड़ती है।
- स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र: व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी), मातृ
 एवं शिश स्वास्थ्य तथा गैर-संचारी रोगों के लिए 1,50,000 केंद्र बनाये गए।
- पीएमजेएवाई: द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है।

कार्यान्वयन

- सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता (ईएचसीपी): नकदी रहित सेवाओं के लिए सार्वजनिक और निजी अस्पतालों का नेटवर्क तैयार किया गया है।
- **कवरेज:** इसमें 1350 प्रक्रियाएं, निदान और दवाएं शामिल हैं।

प्रगति और विकास

- हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन: 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, लगभग 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
- पायलट लॉन्च: 1280 से अधिक अस्पतालों के साथ आईटी प्रणालियों और राज्य की तैयारियों का परीक्षण।
- प्रशिक्षण: लाभार्थियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएम) को प्रशिक्षित किया गया।

आईटी सिस्टम

- लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस): सेवा केन्द्रों पर सत्यापन के लिए विकसित की गई।
- लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस): अस्पताल के लेनदेन और दावों को स्विधाजनक बनाती है।

🔪 लाभार्थी की पहचान

 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी): लाभार्थियों की पहचान करने और व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए उपयोग किया जाता है।

News in Between the Lines

कल, 11 सितंबर को, भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रस्कार 2024 से सम्मानित किया।

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के बारे में:

- राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को दी गई सराहनीय सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में दिया जाता है।
- पुरस्कार में 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक पदक शामिल है।
- 🖣 यह पुरस्कार केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, निजी, मिशनरी और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को दिया जाता है।
- 🔹 राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सहायक नर्स, दाई, महिला स्वास्थ्य आगंतुकों और नर्सी जैसी श्रेणियों में नर्सिंग उत्कृष्टता का सम्मान करते हैं।

हाल ही में, नागालैंड में, राज्य सरकार ने चुमौकेदिमा, निउलैंड और दीमापुर जिलों में इनर लाइन परमिट (ILP) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

इनर लाइन परमिट के बारे में:

- इनर लाइन परिमट (ILP) एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को सीमित समय के लिए कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमित देता है।
- 📭 इनर लाइन परमिट प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में लागू की गई है।
- इन राज्यों के नागरिकों को छुट दी गई है और आगंत्क ILP की अनुमत अविध से अधिक नहीं रुक सकते हैं।
- इसकी उत्पत्ति 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से हुई है, जिसे ब्रिटिशों ने आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों की स्वदेशी आबादी की रक्षा के लिए पेश किया था।
- विदेशी पर्यटकों को संरक्षित क्षेत्र परिमट (PAP) की आवश्यकता होती है, जो भारतीय नागरिकों के लिए ILP से अलग है।
- इनर लाइन परिमट का उद्देश्य जनसांख्यिकीय प्रवाह को नियंत्रित करके आंदोलन को विनियमित करना, स्वदेशी समुदायों की रक्षा करना और स्थानीय संस्कृति, रीति-रिवाजों और सुरक्षा को संरक्षित करना है।

इनर लाइन परमिट

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल



Face to Face Centres





Current affairs summary for prelims

12 September, 2024

भद्रा टाइगर रिजर्व के बारे में:



- भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित है।
- रिजर्व का आकार तश्तरी जैसा है और इसमें घाटियों और खड़ी पहाड़ियों के साथ उतार-चढ़ाव वाला इलाका है।
- इस क्षेत्र को सबसे पहले 1951 में जगारा घाटी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था और फिर 1974 में इसका नाम बदलकर भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया।

हाल ही में, आक्रामक खरपतवार मिकानिया मिक्रांथा भद्रा टाइगर रिजर्व (बीटीआर) में तेजी से फैल रहा है और इसकी जैव विविधता को खतरा पहुंचा रहा है।

- इसे 1998 में भारत का 25वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
- रिजर्व भद्रा नदी और उसकी सहायक नदियों के पास स्थित है।
- वनस्पति: रिजर्व में शुष्क-पर्णपाती, नम-पर्णपाती, शोला के साथ-साथ सागौन, शीशम, मठी, होन, नंदी और विभिन्न औषधीय पौधे हैं।
- जीव-जंतु: यह रिजर्व बाघ, तेंदुए, ढोल, भारतीय सिवेट और गौर, सांभर, हाथी और भौंकने वाले हिरण जैसे खुर वाले जानवरों का घर है।

हाल ही में गोविंद बल्लभ पंत को उनकी जयंती पर याद किया गया।

गोविंद बल्लभ पंत - (10 सितंबर 1887-7 मार्च 1961)

गोविंद बल्लभ पंत, एक प्रख्यात भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा (तब संयुक्त प्रांत का हिस्सा) के पास खूंट गांव में हुआ था।

योगदान:

- गोविंद बल्लभ पंत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे. उन्होंने असहयोग और सविनय अवजा आंदोलनों में भाग लिया।
- उन्होंने काकोरी षडयंत्र मामले में रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व किया और नमक मार्च के आयोजन और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए जेल गए।
- उन्होंने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पंचायत प्रणाली और कृषि में बड़े सुधार पेश किए।

पुरस्कार और सम्मानः

- गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न (भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान) से सम्मानित किया गया।
- गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान सहित कई संस्थानों का नाम भारत में उनके योगदान को याद करने के लिए उनके सम्मान में रखा गया है।

खबरों में व्यक्तित्व गोविंद बल्लभ पंत

भद्रा टाइगर रिजर्व



POINTS TO PONDER

- हाल ही में राजस्थान के बारां जिले में किस जनजाति के 100 से अधिक कुपोषित बच्चों के मामले सामने आए हैं? **सहरिया**
- किस भारतीय राज्य में देश की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी, जिसकी घोषणा हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? ओडिशा
- हाल ही में भारतीय नौसेना के दो पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान पोत, आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की को किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? **कोचीन शिपयार्ड**
- प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत उत्तरी छत्तीसगढ़ में किस समुदाय की 54 बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा? **पहाड़ी कोरवा जनजाति**
- किस अंतरिक्ष यान ने हाल ही में बुध ग्रह के पास से उड़ान भरी है और 2026 में ग्रह की परिक्रमा शुरू करने की उम्मीद है? **बेपीकोलंबो**

